International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 04, No. 03(II), July - September, 2022, pp. 125-130

भारतीय अर्थव्यवस्था में नकद विहीन के नए रुझान, अवसर और चुनौतियां पर अध्ययन

Devendra Raj Singh*

सार

हर दिन लोग, व्यवसाय, संगठन, समुदाय और सरकार निर्णय लेने, सामान बनाने और सेवाओं को अधिक कुशलता से और अधिक तेज़ी से वितरित करने के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग करते हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं की डिजिटल पहुंच और व्यवसायों की सहायता के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग दोनों को संदर्भित करती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था समाज के लगभग सभी पहलुओं को बदल रही है। डिजिटल अर्थव्यवस्था नया उत्पादकता मंच है जिसे कुछ विशेषज्ञ तीसरी औद्योगिक क्रांति मानते हैं। डिजिटल क्रांति, जिसे इंटरनेट इकोनॉमी या इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के रूप में भी जाना जाता है, से बाजार में विकास के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। डिजिटल अर्थव्यवस्था सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा सक्षम आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों की श्रेणी का वर्णन करती है। इसमें बैंकिंग, खरीदना और बेचना, और इंटरनेट और जुड़े उपकरणों का उपयोग करके शिक्षा या मनोरंजन तक पहुंच जैसी गतिविधियां शामिल हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था से अलग नहीं है। यह सभी उद्योगों और व्यवसायों को प्रभावित करता है। इस तरह के मनी ट्रांजैक्शन में नकदी का उपयोग नहीं किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं को खरीदा और भुगतान किया जाता है।

शब्दकोशः *अर्थव्यवस्था, डिजिटल अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल तकनीक।*

प्रस्तावना

डिजिटल अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था को संदर्भित करती है जिसका आधार कंप्यूटिंग और प्रौद्योगिकी है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को इंटरनेट अर्थव्यवस्था और वेब अर्थव्यवस्था भी कहा जा सकता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था इंटरनेट पर होने वाले सभी आर्थिक लेनदेन के लिए एक सामूहिक शब्द है। इसे वेब अर्थव्यवस्था या इंटरनेट अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है। प्रौद्योगिकी के आगमन और वैश्वीकरण की प्रक्रिया के साथ, डिजिटल और पारंपरिक अर्थव्यवस्थाएं एक में विलीन हो रही हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था को एक ऐसी अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित है, अर्थात यह डिजिटल और कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकियों पर आधारित है। यह अनिवार्य रूप से सभी व्यावसायिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि गतिविधियों को शामिल करता है जो वेब और अन्य डिजिटल संचार प्रौद्योगिकियों द्वारा समर्थित हैं।

जब एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में स्थानांतरित होती है, तो यह बहुत अधिक प्रतिरोध और चुनौतियाँ ला सकती है। लेकिन डिजिटल अर्थव्यवस्था अपने साथ बहुत सारे अवसर और नए पहलू भी लाती है जो न केवल पुरानी या यूं कहें की ऐसी व्यवस्था जिसमें नकद का स्थानांतरण अधिक मात्रा में हो

* Research Scholar, Raj Rishi Bhartrihari Matsya University, Alwar, Rajasthan, India.

रहा हो. को पुनरुद्धार की ओर ले जाती है, बल्कि अर्थव्यवस्था को नए आयाम देती है और नई आर्थिक संरचना देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डिजिटल अर्थव्यवस्था इंटरनेट के माध्यम से भौतिक व्यवसायों को सहजता से संचालित करने के लिए नए उपकरण प्रदान करती है। बड़ी मात्रा में ग्राहकों के साथ–साथ महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए उपयुक्त लक्षित ग्राहकों या उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए भौतिक विपणन को ऑनलाइन से बदला जा सकता है।

साहित्य की समीक्षा

शंकर (2017) के अनुसार डिजिटल अर्थव्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक मनी इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़ावा देने, वित्तीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने और लोगों के बीच डिजिटल लेनदेन की आदतों को फैलाने से साकार होती है। आरबीआई का भुगतान और निपटान विजन दस्तावेज 2018 डिजिटल अर्थव्यवस्था की दिशा में उद्देश्य और दिशानिर्देश देता है। भारत धीरे–धीरे नकदी–केंद्रित से डिजिटल अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो रहा है। डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ अब मिलने लगे हैं क्योंकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल तरीके करने के लिए स्विच कर रहे हैं। पूरा देश पैसे के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है लेनदेन, ई–भुगतान सेवाओं के साथ अभूतपूर्व गति प्राप्त कर रहा है। बड़ी संख्या में व्यवसाय, यहां तक कि स्ट्रीट वेंडर, अब इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार कर रहे हैं, जिससे लोगों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

ओकिलवानी और दुर्गारानी (2017) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का भारतीय अर्थव्यवस्था को और भारतीय समाज को डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का एक प्रमुख कार्यक्रम है। जिसके द्वारा नकद विहीन अर्थव्यवस्था का उदय होना है और अर्थव्यवस्था का डिजिटल रूप से अधिक सशक्त और मजबूत होना एक मुख्य उद्देश्य हैं। डिजिटल इंडिया अगले कुछ वर्षों में आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा और वैश्विक मूल्य के लगभग 40 प्रतिशत हिस्से में अगले दशक में नए विजेता और विक्रेता होंगे। डिजिटल अर्थव्यवस्था के इस बड़े अवसर में भारत के लाखों लोगों के जीवन को बदलने की ताकत है। यह परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण वाहन हो सकता है और यह भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका और प्रभाव का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करने और डिजिटल नवाचार का एक पावरहाउस बनने का अवसर प्रदान कर सकता है।

भुक्त और हिक्स (2019) ने वर्णित किया कि डिजिटल अर्थव्यवस्था विकसित देशों के साथ–साथ विकासशील देशों में भी अब तेजी से बढ़ रही है परंतु डिजिटल अर्थव्यवस्था के अर्थ और आयाम अभी तक भिन्न भिन्न हैं। विकासशील देशों में विशेष रूप से उच्च विकास स्तर के साथ, डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक और राजनीतिक अनिवार्यता तकनीकी नवाचार के साथ जुड़ रही है। इस विकास को निजी क्षेत्र द्वारा, सरकार द्वारा निर्देशित, और नागरिक समाज और अकादमी द्वारा विश्लेषण किया जाना चाहिए। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मापने के लिए अस्पष्ट सीमाओं, खराब डेटा गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण की समस्याओं और बहुत अधिक डिजिटल गतिविधि की अदृश्यता की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई चेतावनियों को स्वीकार करते हुए, हम देखते हैं कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को यहां परिभाषित किया गया है, जो संभवत वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5 प्रतिशत और वैश्विक रोजगार का 3 प्रतिशत है। डिजिटल अर्थव्यवस्था से उत्पन्न हुए अवसरों और उन अवसरों को सफलताओं में परिवर्तित करने के लिए आ रही बाधाओं और विकास कार्यों को अलग तरीके से मापने की आवश्यकता है।

गुलनोरा और रुस्तमोव (2019) आज दुनिया एक नई तकनीकी क्रांति में प्रवेश कर रही है। बैंकों, व्यापार और सेवाओं सहित अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में नई तकनीकों को पेश किया गया है। हमारा शिक्षा मॉडल, हमारा व्यवसाय और हमारी अर्थव्यवस्था इन परिवर्तनों से पिछड़ रही है। अर्थव्यवस्था का विकास वैज्ञानिक प्रगति के संगठन का एक विशेष रूप है जो प्रतिस्पर्धात्मक लाभ और तकनीकी उन्नति सुनिश्चित करता है। नवाचारों के बिना अर्थव्यवस्था के वर्तमान विकास की कल्पना करना असंभव है, जिसका आधार मानव, मुख्य रूप से मानव पूंजी है। मानव पूंजी का डिजिटल प्रौद्योगिकी में संक्रमण इसे परिभाषित करता है। इलेक्ट्रॉनिक

प्रौद्योगिकियों और सेवाओं के विकास पर आधारित अर्थव्यवस्था वाले देशों के रूप में, सूचना और डिजिटल स्थान के विकास और विश्लेषण सहित, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए, हमें डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक राष्ट्रीय अवधारणा विकसित करने की आवश्यकता है, जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के आधार पर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के आधुनिकीकरण का प्रावधान करती है।

शर्मा (2016) के अनुसार यह एक सर्वविदित तथ्य है कि डिजिटल इंडिया कई नवाचारों और तकनीकी प्रगति का परिणाम है। ये लोगों के जीवन को कई तरह से बदलते हैं और समाज को बेहतर तरीके से सशक्त बनाते है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग और मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं। दुनिया भर में त्वरित आर्थिक विकास और नागरिक सशक्तिकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में उभरी हैं। खुदरा स्टोर से लेकर सरकारी कार्यालयों तक रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे द्वारा डिजिटल तकनीकों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। विश्लेषकों के अनुसार, डिजिटल इंडिया योजना 2025 तक सकल घरेलू उत्पाद को + 1 ट्रिलियन तक बढ़ा सकती है। यह सकल–आर्थिक कारकों जैसे सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि, रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

शोध पत्र के उद्देश्य

- डिजिटल अर्थव्यवस्था की अवधारणा को समझना।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था के लाभ हानियां और अवसरों को जानना।
- इस शोध पत्र का उद्देश्य डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से सरकारी क्रियाकलापों में पारदर्शिता और लाभ को समझना भी है।

अनुसंधान क्रियाविधि

इस शोध पत्र का अध्ययन, डाटा और सूचनाओं द्वितीय स्रोतों पर आधारित है। संबंधित पुस्तकों पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, और प्रासंगिक वेबसाइटों से भी सूचना और डाटा एकत्रित किए गए हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था के घटक

डिजिटल अर्थव्यवस्था में विभिन्न घटक शामिल हैं जिनमें सरकारी नीति और विनियमन इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब और बिजली के बुनियादी ढांचे, दूरसंचार उद्योग, डिजिटल सेवा प्रदाता, ई–व्यवसाय और ई–कॉमर्स उद्योग, सूचना और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली, बौद्धिक संपदा अधिकार मानव पूंजी और ज्ञान कार्यकर्ता, अनुसंधान और विकास और उभरती हुई प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन

- पारंपरिक डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटरों की घटती हिस्सेदारी।
- मोबाइल उपकरणों और सेवाओं का बढ़ता महत्व।
- स्मार्ट फोन, टैबलेट, वायरलेस डेटा सेवा, वाईफाई के उपयोग में बढ़ोतरी।
- कंप्यूटिंग सेवाओं का बढ़ता महत्व।
- क्लाउड सेवाएं, वितरित कंप्यूटिंग का बढ़ता प्रचलन।
- अन्य तकनीकी उपकरणों का बढ़ता महत्व।
- संचार उपकरण, विद्युत–चिकित्सा उपकरण का बढ़ता प्रचलन।

डिजिटल अर्थव्यवस्था से सरकार को फायदा

डिजिटल भुगतान विधियों जैसे डिजिटल प्वाइंट ऑफ सेल (डिजिटल पीओएस) यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) मोबाइल वॉलेट मोबाइल प्वाइंट ऑफ सेल (एमपीओएस), आदि को लागू करके, हमारा देश एक डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है डिजिटल अर्थव्यवस्था से सरकार द्वारा देखे जाने वाले कुछ प्राथमिक लाभ निम्न हैं।

- **ब्लेक इकोनॉमी को हटाना**

जब लेनदेन डिजिटल रूप से किए जाते हैं, तो उन पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। किसी भी ग्राहक द्वारा किसी व्यापारी को किया गया कोई भी भुगतान रिकॉर्ड किया जाएगा। इस तरह, अवैध लेनदेन होने का कोई साधन नहीं होगा। नकद–आधारित लेनदेन को प्रतिबंधित करके और केवल डिजिटल भुगतान का उपयोग करके, सरकार प्रभावी रूप से ब्लेक इकोनॉमी को बाहर निकाल सकती है।

- **राजस्व में वृद्धि**

यह डिजिटल अर्थव्यवस्था के सबसे स्पष्ट और सामान्य लाभों में से एक है। जब लेन–देन डिजिटल हो जाते हैं, तो बिक्री और करों की निगरानी करना सुविधाजनक हो जाता है। चूंकि प्रत्येक लेनदेन दर्ज किया जाता है, ग्राहकों को उनकी खरीद के लिए एक बिल मिलेगा, और व्यापारी सरकार को बिक्री कर का भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। यह, बदले में, सरकार के राजस्व में वृद्धि करता है – इस प्रकार देश की समग्र वित्तीय स्थिति में वृद्धि होती है।

- **मानव संसाधन का सशक्तिकरण**

डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने का एक सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह नागरिकों को सशक्तिकरण प्रदान करता है। जब भुगतान डिजिटल हो जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास एक बैंक खाता, एक मोबाइल फोन आदि होना अनिवार्य है। इस तरह, सरकार आसानी से सब्सिडी को सीधे लोगों के आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित कर सकती है। संक्षेप में, लोगों को अब उन प्रोत्साहनों और सब्सिडी को प्राप्त करने के लिए प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है जो वे सरकार से प्राप्त करने के लिए हैं।

- **ई–गवर्नेंस का मार्ग**

पारंपरिक शासन के बजाय तेज, सुरक्षित और अधिक कुशल विकल्प, ई–गवर्नेंस डिजिटल अर्थव्यवस्था का अंतिम परिणाम होगा। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है – इस प्रकार लोगों के लिए यह सुविधाजनक है कि वे यात्रा के दौरान आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें। डिजिटल अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से ई–गवर्नेंस का मार्ग प्रशस्त करेगी, जहां सभी सरकारी सेवाओं की डिलीवरी इलेक्ट्रॉनिक रूप से की जाएगी।

- **नई नौकरियों का सृजन**

डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए बाजारों में नौकरी के अवसरों को बढ़ाने के साथ–साथ सरकार में कुछ मौजूदा व्यवसायों में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की बहुत संभावनाएं हैं। इस तरह देश में बेरोजगारी दर में कमी आना तय है।

- **डिजिटल अर्थव्यवस्था में नए अवसर**

डिजिटल अर्थव्यवस्था ने अर्थव्यवस्था के रूप को परिवर्तित करने के साथ–साथ तकनीकी विकास के कारण संचार की विभिन्न यंत्रों के समावेश के कारण पूंजी के निवेश के नौकरियों के नए नए अवसर भी बनाए हैं।

- **बाजार में डिजिटल खिलाड़ियों का वर्चस्व**

6 जुलाई 2017 को स्टॉक की कीमतों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर सबसे मूल्यवान कंपनियां एपल, एल्फाबेट, माइक्रोसॉफट, अमेजोन और फेसबुक थीं। चीन के अलीबाबा ने कुल मिलाकर सातवां स्थान हासिल किया।

- **डिजिटल प्रौद्योगिकियां के कार्य क्षमता में विस्तार**

जैसा कि एचबीआर डिजिटल इवोल्यूशन इंडेक्स 2017 में कहा गया है, डिजिटल प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग द्वारा सक्षम स्वचालन, बड़ा डेटा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्व अर्थव्यवस्था के 50 प्रतिशत को प्रभावित कर सकती है। वर्तमान तकनीक में 14.6 ट्रिलियन डॉलर मूल्य की 1 बिलियन से अधिक नौकरियों को स्वचालित करने की क्षमता है।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की सफलता के लिए सार्वजनिक नीति

विश्व स्तर पर, अर्थशास्त्रियों को भारत सहित एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक–निजी नीतियों को अपनाना चाहिए। साथ ही, उन्हें पुरानी अर्थव्यवस्था में स्वचालन, डेटा और नई तकनीकों के बेहतर एकीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए। विशेष रूप से स्कूलों में शुरुआती स्तर पर डिजिटल अर्थव्यवस्था में फलने–फूलने के लिए आवश्यक कौशल को पेश करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

डिजिटल अर्थव्यवस्था की चुनौतियां

- भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था माना जाता है जिसमें लेनदेन अधिकतर नकद स्तर पर ही किए जाते हैं भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13 प्रतिशत। लेन–देन मुख्य रूप से नकद में होता हैरू लगभग 95ः लेनदेन नकद में होता है। बड़े आकार की अनौपचारिक/असंगठित क्षेत्र की संस्थाएं और कर्मचारी नकद आधारित लेनदेन को प्राथमिकता देते हैं। उन्हें डिजिटल और फिनटेक साक्षरता की आवश्यकता नहीं है।
- एटीएम का उपयोग मुख्य रूप से नकद निकासी के लिए होता है न कि ऑनलाइन लेनदेन को निपटाने के लिए। लगभग 21 करोड़ रूपया कार्ड सहित बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड हैं, लेकिन करीब 92 फीसदी एटीएम कार्ड का इस्तेमाल केवल नकद निकासी के लिए किया जाता है। एटीएम कार्ड का उपयोग करके केवल निम्न स्तर का डिजिटल भुगतान शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में एक से अधिक कार्ड रखने से ग्रामीण इलाकों में कम पहुंच दिखाई देती है।
- पीओएस में प्वाइंट ऑफ सेल टर्मिनलों की सीमित उपलब्धता और खराब लेनदेन संस्कृति देखी जा सकती है। आरबीआई के अनुसार, जुलाई 2016 के अंत में विभिन्न बैंकों द्वारा विभिन्न स्थानों पर 1.44 मिलियन पीओएस टर्मिनल स्थापित किए गए हैं। लेकिन उनमें से ज्यादातर शहरी/अर्ध–शहरी क्षेत्रों में बने हुए हैं।
- ग्रामीण भारत में मोबाइल इंटरनेट की पहुंच कमजोर बनी हुई है। लेनदेन को डिजिटल रूप से निपटाने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में खराब कनेक्टिविटी है। इसके अलावा, देश के गरीब और ग्रामीण हिस्सों में साक्षरता का निम्न स्तर, प्लास्टिक मनी के उपयोग को व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ाने में समस्या पैदा करता है।
- उपभोक्ताओं की धारणा भी कभी–कभी एक बाधा का काम करती है। डिजिटल लेनदेन का लाभ उन लोगों को भी नहीं दिख रहा है जिनके पास क्रेडिट कार्ड हैं। दूसरी ओर, नकद को सबसे तेज़ माना जाता है। यह सार्वभौमिक रूप से माना जाता है कि नकदी होने से आपको बेहतर मोल भाव करने में मदद मिलती है।
- भारतीय बैंक निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जारी किए गए डिजिटल वॉलेट को संबंधित बैंक की वेबसाइटों पर इस्तेमाल करना मुश्किल बना रहे हैं। यह डिजिटल वॉलेट को फिर से भरने के लिए बैंक खातों के उपयोग पर प्रतिबंध या भुगतान गेटवे तक पहुंच की कमी हो सकती है। बैंकों द्वारा इस तरह के किराए की मांग के व्यवहार के खिलाफ नियामकों को कड़ा रुख अपनाना होगा।
- अधिकांश कार्ड और नकद उपयोगकर्ताओं को डर है कि यदि वे कार्ड का उपयोग करते हैं तो उनसे अधिक शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड के गैर–उपयोगकर्ता क्रेडिट कार्ड के लाभों से अवगत नहीं हैं।
- एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उपभोक्ता संरक्षण कानून और गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का है, जिनके अनुपालन की गारंटी राज्य द्वारा दी जानी चाहिए, एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक उपभोक्ता को यह आश्वासन सरकार द्वारा अथवा सरकारी कानूनों द्वारा मिलना चाहिए कि उनके किया उनके द्वारा किया गया लेन–देन पूर्णता सुरक्षित है और उनकी व्यक्तिगत जानकारी का कहीं कोई दुरुपयोग नहीं किया जा रहा है।

निष्कर्ष

किसी राष्ट्र के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था ही आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण कारक होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था के रास्ते में आने वाले अवरोधों को सरकारी और गैर सरकारी मदद से दूर किया जा सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नया संचार मिले। आने वाले समय में भारत डिजिटल तकनीकों का सबसे बड़ा उपभोक्ता होगा। एक और कारण यह है कि दुनिया भर में, वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंचने के लिए संचार के कई चौनल हैं और डिजिटल चैनल नवीनतम और सबसे सुविधाजनक होता है। निजी क्षेत्र और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, इन समस्याओं का समाधान इस तरह से करना चाहिए जिससे इंटरनेट एक सुरक्षित वातावरण बने और इसके व्यावसायिक विकास में बाधा न आए। डिजिटल क्रांति, जिसे इंटरनेट इकोनॉमी या इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग के रूप में भी जाना जाता है। अगले 30 से 40 वर्षों में नए बाजार विकास के अवसर, रोजगार और मानव जाति के लिए सबसे बड़ा व्यावसायिक अवसर बनने की उम्मीद है। हमें एक अर्थव्यवस्था और एक समुदाय के रूप में, परिवर्तन का जवाब देने और डिजिटल अर्थव्यवस्था के अवसरों को समझने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। नई और उभरती डिजिटल प्रौद्योगिकियां उद्योगों और व्यवसाय के काम करने के तरीके को बदल रही हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां बाजार डिजिटल परिवर्तन के लिए अच्छी तरह से समायोजित हो रहा है। विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक प्रभावों का अभी पता नहीं चल पाया है। यह उम्मीद की जाती है कि यह लंबे समय में कर अनुपालन, वित्तीय समावेशन को बढ़ाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति में सुधार हो सकता है। यह ऋण देने के लिए धन की उपलब्धता में वृद्धि करके, अर्थव्यवस्था भुगतान के डिजिटल तरीके की ओर बढ़ाती है तो लेनदेन लागत को कम करके जीडीपी को बढ़ावा दे सकती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. शंकर, के यू (2017) भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्थारू चुनौतियां और संभावनाएं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च इन मैनेजमेंट स्टडीज, 2(11), 6–11
2. गोकिलवानी, डी.आर., और दुर्गारानी, डी.आर. (2017) भारत में डिजिटल अर्थव्यवस्था का विकास। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, 9(1), 31–39
3. बुख्त, आर, और हीक्स, आर (2017)। डिजिटल अर्थव्यवस्था को परिभाषित, अवधारणा और मापना। डेवलपमेंट इंफॉर्मेटिक्स वर्किंग पेपर, (68)
4. शर्मा, जे (2016)। डिजिटल इंडिया और समाज पर इसका प्रभाव। मानविकी और समाज में अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। विज्ञान, 4(4)।

❖◆❖